

[2010] 6 एस. सी. आर. 1073

रणवीर यादव

बनाम

बिहार राज्य

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 188)

12 मई, 2010

[जी. एस. सिंघवी और अशोक कुमार गांगुली, न्यायाधीशगण]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971/12 (1) स्पष्टीकरण, 2 (ग) (ii), 19 (1) (ख)-न्यायालय की अवमानना-अवमानना कार्यवाही में माफी- अदालत ने कहा:यह निष्पक्ष और अदालत की संतुष्टि के लिए होना चाहिए-जल्द से जल्द संभव अवसर पर माफी की पेशकश की जानी चाहिए-विलंबित माफी शायद ही पश्चाताप को दर्शाती है जो अवमानना को शुद्ध करने का सार है-अदालत कर सकती है क्षमा याचना स्वीकार करने से इनकार करना, हालांकि देर से नहीं, लेकिन वास्तविक पश्चाताप और पश्चाताप के बिना है और केवल बचाव के एक हथियार के रूप में प्रस्तुत किया गया था-तथ्यों, दोषसिद्धि और मुख्य सजा पर अदालत को बाधित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना ने न्यायाधीश को जाने के लिए मजबूर कर दिया, न्यायसंगत-उनका कार्य अदालत के सामने आपराधिक अवमानना का एक स्पष्ट मामला है-कारण बताएँ नोटिस में मुख्य अवमाननाकर्ता ने कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि अपने कार्य को सही ठहराने की कोशिश की-बाद के कारण बताएँ जवाब में माफी की पेशकश की गई जो एक विलंबित माफी थी-सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966-या। XX /नियम 15 (1) (ई)।

बी. एच., बी. एम., पी. एन. और एम. डी. सत्र सुनवाई मामले में आरोपी हैं और अपीलार्थी मामले में गवाह था और जिरह की जानी थी। दुर्भाग्यपूर्ण दिन को उन सभी ने आक्रामक रूप से गरमागरम शब्दों का आदान-प्रदान करके और अदालत में अप्रिय दृश्य पैदा करके कार्यवाही को बाधित कर दिया, जिससे न्यायाधीश को कमरा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय का संदर्भ दिया। उच्च न्यायालय ने इसे अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 (2) के तहत दिए गए संदर्भ के रूप में माना और अवमानकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा- कि अपीलार्थी व्यवधान के लिए जिम्मेदार मुख्य व्यक्ति था, जिसने प्रेरित और उग्र तरीके से कार्य किया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को निचली अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया। उन्हें दो महीने के लिए साधारण कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 2000/-। उच्च न्यायालय ने अन्य अवमानकर्ताओं की अयोग्य माफी स्वीकार कर ली और उन्हें रिहा कर दिया। इसलिए याचिका दायर की गई है

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अदालत ने कहा: 1.1 मामले के तथ्यों और अभिलेख पर सामग्री में, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने कहा कि अपीलार्थी को दिए गए कारण दर्शाओ नोटिस में उसकी कोई अलग भूमिका नहीं बताई गई है और सजा देने के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी का मामला अलग है। वास्तव में अपीलार्थी ने व्यवधान पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाई और इसमें उसकी ओर से अवसर की कोई कमी नहीं थी। उसके खिलाफ आरोपों का जवाब देना। लगाए गए आरोप उसके खिलाफ एक व्यावहारिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए और एक पांडित्यपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है। कारण दर्शाओ नोटिस में आरोपों के सभी घटकों का

उल्लेख किया गया था और अपीलार्थी ने आरोपों को समझा और जवाब दिया। जवाब में कहीं भी अपीलार्थी ने आरोपों को समझने में कोई कठिनाई नहीं उठाई। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपों में किसी भी अस्पष्टता या आरोपों में अपर्याप्त विवरण प्रस्तुत करने के बारे में कोई विवाद उठाया गया था। अपीलार्थी के वकील के इस तर्क को केवल इस न्यायालय के समक्ष और वह भी उचित तथ्यात्मक आधार के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।[पैरा 19] [1081-एफ-एच; 1082-ए-बी]

1. 2. मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के उल्लंघनकारी कार्य विशेष रूप से न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) (ii) के तहत आ रहे हैं। किसी भी न्यायिक कार्यवाही का उचित संचालन उच्च सार्वजनिक महत्व का विषय है क्योंकि यह कानून के शासन से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, जो न्यायिक प्रक्रिया के संवैधानिक तरीके पर आधारित है। इस देश में शासन। यही कारण है कि अधिनियम के निर्माताओं ने अभिव्यक्ति से पहले "प्रवृत्त" शब्दों के साथ हस्तक्षेप किया और "किसी भी न्यायिक कार्यवाही के पाठ्यक्रम" से पहले 'देय' शब्द को जोड़कर इस पर और जोर दिया गया है। विधायिका शब्दों को बर्बाद नहीं करती है। इसलिए, धारा 2 (ग) (ii) में उपयोग किए गए प्रत्येक शब्द को उसका उचित और स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार पढ़ें, धारा 2 (सी) (ii) को एक व्यापक विस्तार दिया जाना चाहिए ताकि इसमें शामिल किया जा सके। इसके भीतर न्यायिक कार्यवाही के नियत पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने का कोई भी प्रयास 'देय' शब्द संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ न्यायिक कार्यवाही का एक स्वाभाविक और उचित मार्ग होना चाहिए।[पैरा 21 और 22] [1082-एफ-एच; 1083-ए]

1.3 धारा 2 (सी) (ii) को न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता, नियमितता और शुद्धता के अलावा सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। यह सिद्धांतों पर आधारित है। उच्च सार्वजनिक नीति। यही कारण है कि अवमानना की शक्ति को सुपीरियर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड

की एक अंतर्निहित विशेषता कहा जाता है। यह शक्ति अधीनस्थ न्यायपालिका को नहीं दी गई है, लेकिन एक उपयुक्त मामले में, अधीनस्थ न्यायपालिका अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत उच्च न्यायालय को संदर्भित कर सकती है। इस प्रकार, जब उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत एक संदर्भ पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो यह वस्तुतः अधीनस्थ न्यायपालिका के संरक्षक के रूप में अपनी कार्यवाही को आक्रोश और अपमान से बचाने के लिए उसी का प्रयोग कर रहा है। इस तरह की शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' होने के नाते और राज्य में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण होने के नाते उस राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका पर अपने अधिकार क्षेत्र का 'मूल रूप से' निर्वहन कर रहा है। इसलिए, धारा 15 (2) के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति की प्रकृति में कुछ है। वह अधिनियम जो इसे कर्तव्य के साथ जोड़ता है। कर्तव्य स्पष्ट रूप से कानून के शासन को बनाए रखना है। लेकिन एक सवार है। अवमानना शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और उचित मामला और इसलिए उच्च न्यायालय को यह काम सौंपा गया है। [पैरा 23 और 24] [1083-बी-ई; 1084-ए]

1.4 अपीलार्थी के अपमानजनक कार्य न्यायालय के समक्ष अवमानना का गठन करते हैं। जब अदालत के सामने अवमानना होती है, तो लोगों का विश्वास न्याय प्रशासन को एक गंभीर झटका लगता है और न्यायपालिका का बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए, अपीलार्थी के अपमानजनक कार्य निश्चित रूप से न्यायिक कार्यवाही के नियत पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप के दायरे में आते हैं और न्यायालय के सामने आपराधिक अवमानना का एक स्पष्ट मामला है। उच्च न्यायालय, आक्षेपित निर्णय में अपीलार्थी को दोषी ठहराने में सही था और इसमें भी उसे उस सजा से दंडित करना जो उसने दी है। यह कारण दर्शाओ नोटिस में दिखाई देता है, जो इसके द्वारा दिया गया था अपीलार्थी ने शुरू में कोई माफी नहीं मांगी। बल्कि अपीलार्थी ने न्यायसंगत ठहराने की कोशिश की। बाद में कारण दर्शाएँ जवाब

में माफी की पेशकश की गई। इसलिए, यह एक विलंबित माफी है।[पैरा 25 और 26]
[1084-बी-ई]

1.5. अधिनियम की धारा 12 (1) के स्पष्टीकरण के तहत, अदालत माफी को अस्वीकार कर सकती है यदि अदालत को पता चलता है कि इसे सही नहीं बनाया गया था। धारा 12 के तहत, यह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि माफी अदालत की संतुष्टि के लिए होनी चाहिए। इसलिए, अदालत का यह दायित्व नहीं है कि वह माफी की पेशकश होते ही उसे स्वीकार कर ले। क्षमा याचना स्वीकार किए जाने से पहले, न्यायालय को यह पता लगाना चाहिए कि यह वास्तविक है और न्यायालय को संतुष्ट करता है। हालांकि, अदालत केवल इसलिए माफी को अस्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि यह योग्य और सशर्त है बशर्ते अदालत को लगे कि यह सही है।[पैरा 27] [1084-ई-जी]

1.6. अवमानना कार्यवाही में जल्द से जल्द माफी मांगी जानी चाहिए। एक विलंबित माफी शायद ही 'पश्चाताप' को दर्शाती है जो कि है अवमानना को शुद्ध करने का सार '। कई मामलों में विलंबित माफी के अलावा इस तरह की माफी तब तक स्वीकार नहीं की जाती है जब तक कि यह प्रामाणिक न हो। भले ही इसमें देरी न हो, जहां माफी वास्तविक पश्चाताप और पश्चाताप के बिना है और केवल बचाव के हथियार के रूप में प्रस्तुत की गई थी, न्यायालय इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकता है।[पैरा 28,30 और 33] [1084-जी; 1085-8-सी, एफ]

1.7 उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाता है। अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सजा काटनी है। अन्य उत्तरदाताओं पर जारी किए गए नोटिसों को खारिज कर दिया जाता है।[पैरा 34] [1085-जी]

देबब्रत बंदोपाध्याय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य ए. आई. आर 1969 एस. सी 189; प्राचार्य, रजनी पारेख आर्ट्स, के. बी. कॉमर्स और बी. सी. जे. साइंस कॉलेज,

खंभात और अन्य बनाम.महेंद्र अंबालाल शाह 1986 (2) एस. सी. सी. 560; सचिव, हैलाकांडी बार एसोसिएशन बनाम असम राज्य और अन्य (1996) 9 एस. सी. सी. 74; चंद्र शशि बनाम अनिल कुमार वर्मा (1995) 1 एस. सी. सी. 421, संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ:

ए. आई. आर 1969 एस. सी 189	संदर्भित किया गया।	पैरा 29
1986 (2) धारा 560	संदर्भित किया गया।	पैरा 31
(1996) 9 एससीसी 74	संदर्भित किया गया।	पैरा 32
(1995) 1 सेक 421	संदर्भित किया गया।	पैरा 33

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 2009 की आपराधिक अपील सं. 188।

मूल सी. आर. विविध में अवमानना क्षेत्राधिकार में पटना में न्यायिक उच्च क्षेत्राधिकार के दिनांक 03.09.2008 के निर्णय और आदेश से (डी. बी.) 2008 की सं. 8.

पी.एस.मिश्रा, कुमार राजेश सिंह, शिशिर पिनाकी, थथगत एच.बर्धन, उपेंद्र मिश्रा, ध्रुव के. आर. अपीलार्थी की ओर से झा और निरंजना सिंह।

नागेंद्र राय, पी. एच. पारेख, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, समीर पारेख, अजय कुमार झा, सोमनाद्री गौर, पल्लवी श्रीवास्तव (पारेह एंड कंपनी के लिए) शांगतानु सागर, स्मारहर और टी. महिपाल प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय गांगुली, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया

1. यह अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 (1) (बी) के तहत एक वैधानिक अपील है, जिसे उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के आदेश XXI नियम 15 (1) (ई) के साथ पढ़ा जाए।(डीबी) 2008 की आपराधिक विविध संख्या 8

2. कथित मूल प्रकीर्ण(डीबी) 2008 की संख्या 8 एक घटना के बारे में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, खगड़िया द्वारा दिनांक 22.4.2008 को एक संचार के माध्यम से एक संदर्भ था जो 13 फरवरी, 2008 को उनके न्यायालय में हुआ था। उच्च न्यायालय ने इसे न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (इसमें इसके पश्चात्, अधिनियम) की धारा 15 (2) के अधीन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, खगड़िया (इसमें इसके पश्चात्, न्यायाधीश) द्वारा किए गए निर्देश के रूप में माना।

3. न्यायाधीश द्वारा निर्देश इस कारण से किया गया था कि 13.02.2008 को सत्र परीक्षण संख्या 46/93 के दौरान, कथित अवमाननाकर्ताओं में से पांच एक तरफ थे और छठे अवमाननाकर्ता, अपीलकर्ता रणवीर यादव, दूसरी तरफ थे और उन सभी ने आक्रामक रूप से गर्म शब्दों का आदान-प्रदान करके और न्यायालय में अप्रिय दृश्य पैदा करके कार्यवाही को बाधित किया था। न्यायालय की मर्यादा और गरिमा को इतना अधिक खतरा था कि न्यायाधीश को ऊपर उठने के लिए मजबूर होना पड़ा।

4. छह अवमाननाकर्ताओं में से भरत यादव, बिमल यादव, अजय यादव, पांडव यादव और मदन यादव सत्र परीक्षण संख्या 46/93 में आरोपी हैं। अपीलार्थी रणवीर यादव, मामले में एक गवाह और उस दिन, अर्थात् 13.02.2008 को जिरह की जानी थी.

5. उच्च न्यायालय ने ऐसे निर्देश के आधार पर 11.07.2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि कथित अवमाननाकर्ताओं को निर्देश में दिए गए उनके कार्यों के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए।

6. पहले पांच अवमाननाकर्ताओं द्वारा दायर संयुक्त हलफनामों में, उन्होंने अशांति पैदा करने के लिए माफी मांगी और कहा कि हंगामे के लिए मुख्य व्यक्ति अपीलकर्ता रणवीर यादव था। उन्होंने कहा कि यह दृश्य उनके द्वारा अपनी जिरह में देरी करने के लिए बनाया गया था।

7. मदन यादव, जो 76 वर्षीय है और सत्र परीक्षण संख्या 46/93 के अभियुक्तों में से एक है, द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ महत्वपूर्ण है। मदन यादव ने कहा कि अपीलकर्ता 1998 में मदन के पुत्र की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। उस मामले में अपीलार्थी को केवल उच्च न्यायालय के आदेशों पर आरोप तय करने के उद्देश्य से निचली अदालत के समक्ष पेश किया जा सकता था। मदन ने आगे कहा कि उन्हें झूठी पुलिस शिकायत के आधार पर अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक मामले में झूठा फंसाया गया था अपीलार्थी के भाई द्वारा लगाए गए आरोप। मदन के निहितार्थ का मुख्य कारण अपने पुत्र की हत्या से संबंधित पहले के मामले को वापस लेने के लिए उस पर दबाव डालना है और यह मामला अपीलार्थी के खिलाफ लंबित है।

8. इन तथ्यों पर गौर करने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता कई मौकों पर अपने अनुयायियों के साथ निचली अदालत में आया था, जिन्होंने अदालत में उपद्रव पैदा करने में उसकी मदद की थी। यह भी पाया गया कि कई अतिरिक्त लोक अभियोजकों ने अपीलकर्ता से प्राप्त धमकियों और अभिवास के मद्देनजर अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामलों से खुद को वापस ले लिया था। घटना की तारीख पर, यहां तक कि बचाव पक्ष के वकील को भी नहीं बखशा गया, जैसा कि रक्षा पक्ष के वकील द्वारा पीठासीन अधिकारी को लिखे गए पत्र से स्पष्ट है।

9. उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी ने बीमारी और नियत तिथियों पर उपस्थित न होने के बहाने विभिन्न अवसरों पर अपनी प्रतिपरीक्षा को स्थगित करने और उसमें विलंब करने में भी कामयाब रहा था।

10. उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक मामला, जिसमें अपीलार्थी एक अभियुक्त था, अपीलार्थी द्वारा दी गई धमकियों और अभित्रास को ध्यान में रखते हुए दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया था।

11. अपीलार्थी रणवीर यादव द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ मामले में, उसने 13 फरवरी, 2008 को यह कहते हुए अपने व्यवहार को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की कि 12 दिसम्बर, 2007 को न्यायालय को सूचित किया गया था कि समझौता किया जाएगा। लेकिन वह तब नाराज हो गए जब अतिरिक्त लोक अभियोजक अदालत के समक्ष पेश हुए और उन्होंने सोचा कि वह लोक अभियोजक के आदेश के बिना पेश हुए थे। अपीलार्थी के ऐसे औचित्य पर उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी का साक्षी होने का लोक अभियोजक की उपस्थिति से कोई संबंध नहीं था और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी का दुर्यवहार न्यायोचित नहीं था।

12. 1 मार्च, 2008 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में अपनी असफलता के संबंध में, अपीलार्थी ने कहा कि उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, जिसकी उसने मांग की थी।

13. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सभी विचारक आपराधिक अवमानना करने के दोषी थे और उसने दो अभियोजन अधिवक्ताओं के साथ-साथ बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के पत्रों पर भरोसा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यवधान के लिए

मुख्य व्यक्ति अपीलकर्ता था जिसने कार्यवाही के उचित संचालन में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित और उच्च-स्तरीय तरीके से कार्य किया।

14. उच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय में व्यवधान के लिए मुख्य अपराधी अपीलार्थी था। अन्य पांच अवमाननाकर्ताओं की बिना शर्त माफी स्वीकार करते हुए और उन्हें चेतावनी और गंभीर चेतावनी के साथ छोड़ देते हुए, अपीलकर्ता को 2,000/- रुपये के जुर्माने के साथ दो महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी और चूक होने पर अपीलकर्ता को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ा था।

15. इस न्यायालय ने इस अपील में नोटिस/सूचना जारी करते हुए 28 अगस्त, 2009 को एक आदेश पारित किया जिसमें अन्य पांच अवमानना करने वालों से कारण बताओ कि उच्च न्यायालय का आदेश क्यों दिया गया उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार करना और उन्हें छोड़ने का निर्देश देना अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच, अपीलार्थी की गिरफ्तारी पर एक और रोक लगाने का आदेश दिया गया था, जिसके तहत अपीलार्थी को आत्मसमर्पण करने से छूट दी गई थी।

16. जिन पांच अवमाननाकर्ताओं को उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया था, उन्होंने 28.01.2010 को अपना संयुक्त जवाबी हलफनामा दायर किया। बिना शर्त माफी मांगते हुए, उन्होंने वही स्पष्टीकरण दिया है जो उच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया था कि व्यवधान के लिए मुख्य व्यक्ति अपीलकर्ता था। जवाबी हलफनामे के पैरा IV और V में, उन्होंने कहा है कि अपीलार्थी ने एक दुस्साहसिक तरीके से व्यवहार किया और दोनों पक्षों के वकील का दुरुपयोग किया और जांच से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अपीलकर्ता एक बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और आपराधिक पृष्ठभूमि/इतिहास के साथ एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है।

17. इस मामले में अपीलार्थी के विद्वत् वकील/अधिवक्ता ने यह तर्क देने की कोशिश की कि अवमानना की कार्यवाही में उच्च न्यायालय अपीलार्थी को दंडित करके अलग रख नहीं अपना सकता और अन्य अपीलार्थियों को यह अभिनिर्धारित करने के बाद भी कि वे अवमानना के दोषी हैं, बिना दंडित किए जाने देना।

18. विद्वत् वकील/अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी को दिए गए कारण बताओ नोटिस में, उसे कोई अलग भूमिका नहीं दी गई है, इसलिए दंड देने के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उसके साथ अलग तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता है.

19. यह न्यायालय अपीलार्थी के विद्वत् वकील/अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क को समझने में असमर्थ है। मामले के तथ्यों और अभिलेख पर सामग्री में, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का मामला एक अलग आधार पर है। वास्तव में अपीलार्थी ने व्यवधान पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाई और उसके खिलाफ आरोपों का जवाब देने में उसकी ओर से अवसर की कोई कमी नहीं है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को व्यावहारिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें पागलपन से नहीं पढ़ा जा सकता। आरोपों के सभी घटकों को कारण बताओ नोटिस में कहा गया था और अपीलकर्ता ने आरोपों को समझा है और जवाब दिया है। उत्तर में कहीं भी अपीलार्थी ने आरोपों को समझने में कोई कठिनाई नहीं उठाई है। ऐसा नहीं लगता कि कोई विवाद था अपीलार्थी द्वारा आरोपों में किसी अस्पष्टता के बारे में या आरोपों में अपर्याप्त विवरण प्रस्तुत करने के बारे में उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया। अपीलार्थी के विद्वत् वकील/अधिवक्ता के इस तर्क पर केवल इस न्यायालय के समक्ष और वह भी उचित तथ्यात्मक आधार के बिना विचार नहीं किया जा सकता है।

20. अधिनियम की धारा 2 (ग) के तहत आपराधिक अवमानना को परिभाषित किया गया है। इस मामले में शामिल प्रश्नों के समुचित मूल्यांकन के लिए उक्त परिभाषा नीचे दी गई है:---

2 (ग)।"" "आपराधिक अवमानना" "से किसी भी मामले का प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखे गए, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) या किसी भी अन्य कार्य का करना, जो

(i) किसी भी अदालत के अधिकार को प्रभावित करता है या कम करता है या कम करता है।"

(ii) पूर्वाग्रह, या हस्तक्षेप या प्रवृत्ति किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम में हस्तक्षेप करना. या

(iii) किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की ओर प्रवृत्त होता है या बाधा डालने की ओर प्रवृत्त होता है।"

21. मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस मामले में अपीलार्थी के अपमानजनक कार्य विशेष रूप से हैं धारा 2 (ग) (ii) के अंतर्गत आने वाली धारा किसी भी न्यायिक कार्यवाही का उचित संचालन उच्च सार्वजनिक महत्व का मामला है क्योंकि यह कानून के शासन से जुड़ा हुआ है जो इस देश में शासन के संवैधानिक तरीके पर आधारित है।"यही कारण है कि अधिनियम के निर्माताओं ने अभिव्यक्ति से पहले" "करने के लिए" "शब्दों के साथ हस्तक्षेप किया और किसी भी न्यायिक कार्यवाही के अनुक्रम से पहले 'कारण' शब्द जोड़कर इस पर जोर दिया गया है।"

22. हमें यह याद रखना चाहिए कि विधायिका शब्दों की बर्बादी नहीं करती। अतः धारा 2 (ग) (ii) में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को उसका उचित और स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार धारा 2 (ग) (ii) को व्यापक विस्तार दिया जाना चाहिए ताकि न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम में हस्तक्षेप करने के किसी प्रयास को भी इसमें शामिल किया जा सके "इस संदर्भ में" "इयू" "शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ न्यायिक कार्यवाही का स्वाभाविक और उचित मार्ग होना चाहिए।"

23. अतः, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि धारा 2 (ग) (ii) का अधिनियमन किसी न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता, नियमितता और शुद्धता के अलावा संरक्षण के लिए किया गया है। यह हम, दोहराते हुए, यह उच्च सार्वजनिक नीति के सिद्धांतों पर आधारित है। यही कारण है कि अवमानना शक्ति को अभिलेख श्रेष्ठ न्यायालय का एक अंतर्निहित गुण कहा जाता है। यह शक्ति अधीनस्थ न्यायपालिका को नहीं दी गई है, लेकिन एक उपयुक्त मामले में, अधीनस्थ न्यायपालिका अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत उच्च न्यायालय को संदर्भ दे सकती है, जैसा कि इस मामले में किया गया है। इस प्रकार, जब उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत किसी संदर्भ पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो वह वास्तव में अपनी कार्यवाहियों को आक्रोश और अपमान से बचाने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका के संरक्षक के रूप में उसी का प्रयोग कर रहा है। ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' और राज्य का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होने के नाते उस राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका पर 'लोको पेरेट्स' में अपनी अधिकारिता का निर्वहन कर रहा है। इसलिए, अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति की प्रकृति में कुछ ऐसा है जो इसे कर्तव्य के साथ जोड़ता है। यह स्पष्ट है कि कर्तव्य कानून के शासन को बनाए रखना है। यहां हम लॉर्ड चांसलर अर्ल केयर्न्स के विचारों को याद कर सकते हैं, जिन्होंने

कर्तव्य के साथ शक्ति की अवधारणा दी थी, जो सबसे शालीन अभिव्यक्ति थी और जिसे मैं उद्धृत करता हूँ:

“..... परन्तु किसी वस्तु की प्रकृति में कुछ हो सकता है जो हमें कुछ करने की शक्ति प्रदान करता है । हमारे उद्देश्य भी हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करी है, हमारी परिस्थिति में कुछ करने में सहायक होती है, व्यक्ति के पद या पदवी भी कुछ करने के लिए संकेत करती है, हमारी मन शक्ति भी कुछ करने में सहायक होती है ।”

[*जूलियस बनाम लार्ड बिशप ऑफ ऑक्सफोर्ड और अन्य*, 5 ए. सी. 214 (एच. एल.) 222-223]

24. ये शब्द आज भी एक अजीब मर्मस्पर्शी गूंज रहे हैं। लेकिन एक सवारी है। अवमानना की शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी और उचित मामले में किया जाना चाहिए और यही कारण है कि उच्च न्यायालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

25. अपीलार्थी के आपत्तिजनक कार्य न्यायालय के समक्ष अवमान का गठन करते हैं। जब न्यायालय के सामने अवमानना होती है तो न्याय के प्रशासन में लोगों के विश्वास को गहरा झटका लगता है और बहुमूल्य न्यायिक समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए, अपीलार्थी के आपत्तिजनक कार्य निश्चित रूप से न्यायिक कार्यवाही के उचित अनुक्रम में हस्तक्षेप की परिधि के भीतर आते हैं और न्यायालय के समक्ष आपराधिक अवमानना का स्पष्ट मामला हैं।

26. उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय में, इसलिए, अपीलार्थी को दोषी ठहराने में और उसे दी गई सजा से दंडित करना। यह कारण बताओ नोटिस में दिखाई देता है, जो अपीलार्थी द्वारा दिया गया था, शुरू में उसने कोई माफी की पेशकश नहीं की। इसके बजाय

अपीलार्थी ने औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की। बाद में कारण बताओ जवाब में माफी की पेशकश की गई। इसलिए यह देर से मांगी गई माफी है।

27. यह अंकित किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 12 (1) के स्पष्टीकरण के तहत, न्यायालय क्षमा याचना को अस्वीकार कर सकता है यदि न्यायालय यह पाता है कि इसे प्रामाणिक नहीं बनाया गया था। धारा 12 के तहत यह बहुत स्पष्ट किया गया है कि माफी न्यायालय की संतुष्टि के लिए होनी चाहिए। इसलिए, यह न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं है कि वह माफी की पेशकश करते ही उसे स्वीकार कर ले। किसी माफी को स्वीकार करने से पहले, न्यायालय को यह अवश्य ही पता लगाना चाहिए कि यह वास्तविक है और न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार है। तथापि, न्यायालय क्षमा याचना को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं कर सकता कि वह योग्य और सशर्त है बशर्ते न्यायालय यह पाता हो कि वह वास्तविक है।

28. अवमानना की कार्यवाही में माफी की पेशकश जल्द से जल्द की जानी चाहिए। देर से मांगी गई माफी शायद ही 'अवमानना को दूर करने का सार' दिखाती है।

29. यह न्यायालय देवव्रत बंदोपाध्याय के मामले में और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य ने रिपोर्ट किया ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 189 में यह मत व्यक्त किया गया था कि “क्षमा याचना अवश्य की जानी चाहिए और वह भी स्पष्ट रूप से और शीघ्र अवसर पर। एक व्यक्ति जो देर से माफी मांगता है वह इस जोखिम को पूरा करता है कि उसे इस तरह की माफी के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, शायद ही वह अवमानना को दूर करने का सार दिखाता है (रिपोर्ट के कंडिका 7 पृष्ठ 193 देखें)।

30. कई मामलों में देर से माफी मांगने के अलावा इस तरह की माफी को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक कि यह प्रामाणिक न हो।

31. सिविल/दीवानी अवमानना के एक मामले में भी इस न्यायालय ने निम्नलिखित में अभिनिर्धारित किया:

प्रिंसिपल, रजनी पारेख आर्ट्स, के. बी. कॉमर्स और बी. सी. जे. साइंस कॉलेज, खंभात के मामले और एक अन्य बनाम एस. के. महेन्द्र अम्बालाल शाह ने 1986 (2) एस. सी. सी. 560 में बताया कि देर से माफी मांगने से वादियों को न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और तदनुसार न्यायालय ने माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया (रिपोर्ट का कंडिका 7 पृष्ठ 566 देखें)।

32. सचिव, हैलाकांडी बार एसोसिएशन के मामले में समान रूप से एसोसिएशन बनाम असम राज्य और अन्य में रिपोर्ट किया गया। (1996) 9 एस. सी. सी. 74 के मामले में, इस न्यायालय ने आपराधिक अवमानना के एक मामले में माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो देर से दी गई थी। अदालत ने कहा कि इस तरह की देर से मांगी गई माफी स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि इसे सद्भाव से नहीं दिया गया है (कंडिका 24 पेज 82 देखें)।

33. यहां तक कि यदि यह विलंब नहीं किया जाता है जहां माफी बिना किसी वास्तविक खेद और पछतावा के है और केवल बचाव के हथियार के रूप में दी गई थी, तो न्यायालय इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। (देखें) चन्द्र शशि बनाम अनिल कुमार वर्मा, (1995) 1 एससीसी 421)।

34. उपर्युक्त कारणों से, अपील विफल हो जाती है, उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है। अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सजा काटनी है। अन्य प्रतिवादियों भारत यादव, बिमल यादव, अजय यादव, पांडव यादव और मदन यादव को जारी किए गए नोटिस को डिस्चार्ज कर दिया गया है।

एन.जे.

अपील खारिज की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।